



राजस्थान सरकार

युवा शक्ति को अवसर
राजस्थान
को नई उड़ाननिष्पक्ष, पारदर्शी और
पेपर लीक रहित भर्तियां

रोजगार, कौशल विकास, भर्ती, स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से युवाओं के सशक्त भविष्य का निर्माण

रोजगार एवं भर्ती

- 1 लाख 78 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां
- 51,427 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण- भर्ती प्रक्रियाधीन
- 81,023 पदों पर भर्तियों की परीक्षा
- 70,031 पदों पर भर्ती की तैयारी

टेक्नोलॉजी एवं भविष्य

- राजस्थान AI-ML पॉलिसी लागू
- AVGC-XR पॉलिसी से एनीमेशन, गेमिंग और डिजिटल रोजगार को बढ़ावा
- Rajasthan Digi Fest 2026 का सफल आयोजन

पारदर्शी भर्ती

- भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी का गठन
- 569 आरोपियों की गिरफ्तारी, 157 एफआईआर दर्ज
- 410 भर्ती परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित

उच्च शिक्षा एवं अवसर

- PRIME योजना से मेधावी विद्यार्थियों को रिसर्च और इंटरनशिप के अवसर
- Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDP) शुरू
- EV, Renewable Energy, BFSI, HR और Tourism जैसे नए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू

कौशल विकास एवं शिक्षा

- 3.58 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
- 76 नए राजकीय महाविद्यालय स्थापित
- 88,724 विद्यार्थियों को टैबलेट/लैपटॉप वितरण
- 42,509 युवाओं को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ

खेल एवं युवा सशक्तिकरण

- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सफल आयोजन
- मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना लागू
- राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोटेंशियल (RTOP) योजना शुरू

युवा कल्याण

- Rajasthan Coaching Centres (Control & Regulation) Bill लागू
- माय भारत पोर्टल पर 19.40 लाख से अधिक युवा पंजीकृत, देश में दूसरा स्थान

स्टार्टअप एवं नवाचार

- राज्य में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 8,780
- स्टार्टअप निवेश ₹250 करोड़ से बढ़कर ₹1,054 करोड़
- 9 इंक्यूबेशन सेंटर और 65 लॉन्चपैड स्थापित
- 1,062 स्टार्टअप्स को ₹33.94 करोड़ की फंडिंग

जो खुद पंजाब में खेमेबाजी में लगे हैं, वो राजस्थान में पार्टी में एकता कैसे लाएंगे?

पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस में सभी को यही चिंता सता रही है

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान के प्रभारी एआईसीसी महासचिव एस.एस. रंधावा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल लिया है। रंधावा जयपुर आने वाले हैं, जहां उन्हें विभिन्न जिलों में आपस में लड़ रहे कांग्रेस नेताओं के बीच एकता कायम करने की कोशिश करनी है।

रंधावा राजस्थान में पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा के पूर्ण समर्थन में हैं। दोनों जाट हैं और दोनों मिलकर राज्य में दूसरे समुदायों को पीछे धकेल कर जाटों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं।

लेकिन अपने गृह राज्य पंजाब में रंधावा असहमति, गुटबाजी और खींचतान के केन्द्र बन गए हैं और उन्होंने पंजाब के पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

राजस्थान के कांग्रेस नेता अब उन पर उंगली उठा रहे हैं और उन्हें पाखंडी बता रहे हैं।

■ चिंता का विशेष कारण यह है कि रंधावा, चूंकि राजस्थान के प्रभारी महासचिव हैं, इसलिए राज्य के पंचायत चुनावों में टिकट वितरण की जिम्मेवारी उन्हीं पर रहेगी।

■ चर्चा है कि पंजाब में रंधावा, अमित शाह से मुलाकात के बाद चन्नी के साथ मिलकर पंजाब के पीसीसी अध्यक्ष राजा वडिंग के खिलाफ गुटबाजी कर रहे हैं।

■ यह भी चर्चा थी कि पंजाब में उनके बगावती तेवरों के कारण उन्हें राजस्थान के प्रभारी पद से हटाया जाएगा, पर, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन पर वेणुगोपाल का हाथ है।

उनका सवाल है कि जब रंधावा खुद राजस्थान और पंजाब, दोनों राज्यों में एक-एक गुट के नेता बने हुए हैं, तो वे कांग्रेस के विभिन्न गुटों के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं।

राजस्थान कांग्रेस कई गुटों में बंट चुकी है : अशोक गहलोत, डोटासरा, जूली, सचिन पायलट और इसी तरह

के कई अन्य गुट हैं।

सवाल यह उठ रहा है कि क्या राजस्थान में होने वाले महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट बांटने के मामले में रंधावा सभी के साथ न्याय कर पाएंगे।

नेताओं का कहना है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए यह चुनाव बेहद

महत्वपूर्ण है। चूंकि भाजपा हर दिन कमजोर होती जा रही है, इसलिए कांग्रेस के पास अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है। लेकिन पार्टी नेतृत्व का अभी राज्य के मुद्दों पर ध्यान नहीं है।

रंधावा के पाला बदलने, और कथित तौर पर अमित शाह के कहने पर पीसीसी अध्यक्ष राजा के बजाय चन्नी का साथ देने के बाद, जोरदार चर्चा थी कि उन्हें राजस्थान के प्रभारी पद से हटाया जा सकता है।

लेकिन अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सवाल यह है कि उनके साथ क्या किया जाएगा?

और इसके अलावा, वेणुगोपाल लगातार उनका बचाव कर रहे हैं।

रंधावा का जयपुर दौरा, जो कल होना था, अब 17 तारीख तक टाल दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या वे खुद को एक ऐसे निष्पक्ष और निर्गुट नेता के रूप में पेश कर पाते हैं, जो सिर्फ जाट नहीं, बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ न्याय कर सके।

रूस ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ बनाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। “बार एंड बेच” की रिपोर्ट के अनुसार, “रूलोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू” ने बताया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.

■ यूक्रेन के ओशादबैंक के साथ विवाद पर इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में होने वाली सुनवाई में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ को अपना प्रतिनिधि बनाया है।

चंद्रचूड़ एक इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह ट्रिब्यूनल यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशादबैंक द्वारा लाए गए एक विवाद की सुनवाई कर रहा है। यह मामला रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और सैन्य अभियानों के कारण बैंक के कामकाज

टेक इट और लीव इट- शाह

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। लम्बी चुप्पी और दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा से गायब रहने के बाद, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि वे सदन में आने, बहस में हिस्सा लेने और उनसे पूछे जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

यह पेशकश संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन से एक दिन पहले आई है। पूरा सत्र लगभग बेकार चला गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों

■ वी हैव लैफ्ट इट- राहुल।

■ गतिरोध वैसे का वैसे बरकरार।

ही संसद के दोनों सदनों में नहीं आए। काफी आलोचना और खराब प्रचार के बाद, अमित शाह जाहिर तौर पर इस धारणा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि गृह मंत्री डरे हुए हैं और छात्रों पर पैलेंट गन चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल पर विपक्ष के हमले का सामना नहीं करना चाहते।

सवाल वही हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं हैं।

राहुल गांधी ने इस पेशकश को नज़रअंदाज़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और देश को किसी भाषण की जरूरत नहीं है। वे पहले सवाल का जवाब चाहते हैं और उसके बाद बहस।

(श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

टाटा संस के प्रमुख चंद्रशेखरन पद त्याग करेंगे

चंद्रशेखरन ने कहा, उन्होंने यह फैसला इसलिए किया है, क्योंकि कंपनी के एक बोर्ड सदस्य ने उनके कार्यकाल विस्तार का समर्थन नहीं किया था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने आज शेयरधारकों के साथ तनाव और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के साथ अपना कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मतभेदों के बीच पद से इस्तीफा दे दिया।

चंद्रशेखरन ने अपने बयान में कहा कि अगले साल फरवरी में उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म होने पर वे दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं करेंगे।

चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के एक सदस्य ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।

उन्होंने अपने बयान में लिखा, “सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे अगले कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था और इसकी सिफारिश की थी। टाटा संस की

■ चंद्रशेखरन ने कहा कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने का फैसला किया था और टाटा संस की नॉमिनेशन एंड रैम्युनेरेशन कमटी ने भी इसे स्वीकार किया था।

■ पर, जब 24 फरवरी 2026 को टाटा संस के बोर्ड के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया तो एक सदस्य ने समर्थन नहीं दिया और सर्वसम्मत समर्थन नहीं मिलने से मैंने इसे तब टाल दिया और अब 6 माह बाद भी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है तो मैंने यह निर्णय लिया है।

नॉमिनेशन एण्ड रैम्युनेरेशन कमटी तथा बोर्ड ने भी इसे रिफाई किया और इसकी सिफारिश की। इसके बाद यह प्रस्ताव 24 फरवरी 2026 को टाटा संस के बोर्ड के सामने रखा गया। लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि बोर्ड के एक सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया। सर्वसम्मत समर्थन नहीं मिलने के कारण मैंने इस फैसले को टालने का निर्णय लिया।”

चंद्रशेखरन ने कहा कि बोर्ड की बैठक को छह महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल पाया है।

उन्होंने कहा, “टाटा संस एक बहुत बड़ा संस्थान है और कई महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाएं इस समय बेहद अहम चरण में हैं। यह जरूरी है कि फरवरी 2027 के बाद समूह का नेतृत्व करने के लिए एक नेता की नियुक्ति हो।

सरकार ने एफसीआर बिल पारित कराने के लिए जेपीसी का रास्ता चुना

सरकार ने विदेशी फंडिंग के नियमन को कठोर बनाने के लिए यह संशोधन किया और इसके लिए वह हितधारकों की चिंताओं और राजनैतिक प्रभावों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। मोदी सरकार द्वारा फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेम्युलेशन) अमेंडमेंट बिल (विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक), 2026 को जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के पास भेजने का फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार विदेशी फंडिंग के नियमन को और कड़ा करते हुए, संसदीय गतिरोध, हितधारकों की चिंताओं और राजनीतिक प्रभावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।

25 मार्च, 2026 को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मुख्य रूप से एफसीआरए, 2010 में संशोधन करना है। इसके तहत, एक निर्दिष्ट प्राधिकरण (डेंजिमेंटेड

■ सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगरानी को विधेयक का मुख्य आधार बताया है।

■ विपक्षी दलों का आरोप है कि यह विधेयक गैर सरकारी संगठनों, अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है।

अर्था(रिटी) गठित करने का प्रस्ताव है, जो किसी संगठन का पंजीकरण रद्द होने, स्वेच्छा से वापस लिए जाने या उसकी अवाधि समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अंशदान और उससे बनाई गई संपत्तियों का प्रबंधन तथा निपटान करेगा।

सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य उन प्रशासनिक खामियों को दूर करना है, जिनके कारण अनिश्चितता और संभावित दुरुपयोग की स्थिति पैदा

होती है। इसके तहत, संपत्तियों को अस्थायी रूप से सरकार के अधिकार में रखने और संगठन का पंजीकरण दोबारा बहाल होने पर उन्हें वापस करने का प्रावधान होगा। साथ ही, पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को सुरक्षित रखने और, समुदाय या विचारधारा की परवाह किए बिना, सभी संगठनों पर नियम समान रूप से लागू करने की बात कही गई है।

(श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

‘जल्दी आयेगा जंतर मंतर सीजन -2’

नई दिल्ली, 12 अगस्त। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर के सीजन-2 को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने लोगों को बताया है कि जंतर-मंतर का सीजन-2 जल्दी ही आएगा।

अभिजीत दीपके ने कहा, बहुत से लोग इस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर-मंतर का सीजन 2 कब शुरू

■ कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने घोषणा की।

होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जंतर-मंतर का सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वे लोग उन्हें वॉलंटियर्स मीट के लिए हॉल नहीं मिलने दे रहे। दीपके ने आज बुधवार को कहा कि आज दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट होनी थी, दूर-दूर से हमारी पार्टी से जुड़े लोग आए थे, लेकिन हमारी मीटिंग नहीं होने दी जा रही।

ऑटो -टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य

नई दिल्ली, 12 अगस्त। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता को और सख्त कर दिया

■ सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम में संशोधन करते हुए चालकों के लिए मराठी जानना अनिवार्य कर दिया है, भाषा नहीं जानने पर तीन माह तक लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान बनाया।

है। बुधवार को सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 में संशोधन करते हुए कड़े नियमों और दंड का प्रावधान किया है। नए नियमों में (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

लिए उपयुक्त है। परन्तु हैरानी की बात है कि 20 फरवरी 2026 को नगर निगम ने उक्त टेंडर को रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिए और कोई कारण भी नहीं बताया। उल्लेखनीय है कि एक महीने बाद ही 12 मार्च 2026 को नगर निगम ने उन्हीं शर्तों के साथ पुनः निविदा आमंत्रित करी। परन्तु दो ही महीने बाद 9 अप्रैल 2026 को इस निविदा को भी रद्द कर दिया और रद्द करते हुए नोटिस में केवल यह जानकारी दी कि निविदा को “अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है”। तत्पश्चात नगर निगम ने 4 जून 2026 को पुनः एक नई निविदा आमंत्रित की परन्तु इसमें यह शर्त लगा दी कि निविदाकार के पास ऐसी गाडियां होनी चाहिए, जिनकी रजिस्ट्री जनवरी 2026 से पहले की हो।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि तीसरी निविदा की शर्तों में मनमाने तरीके से फेर- बदल केवल (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

निजी पूंजी जुटाने में विकास बैंकों की भूमिका अहम: सीतारमण

जयपुर में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गर्वनरों की दो दिवसीय बैठक आयोजित

जयपुर। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख इंजन हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर निजी पूंजी जुटाने के मामले में सदस्य देशों के सामने कई समान संरचनात्मक चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती केवल पूंजी उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए भरोसेमंद, स्थिर और पूर्वानुमेय

■ ‘ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास की प्रमुख इंजन, निवेशकों का भरोसा और स्थिरता जरूरी’

माहौल तैयार करने की भी है। जयपुर में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गर्वनरों की बैठक के दौरान द रोल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल इन मंबर कंट्रीज विषय पर आयोजित सेमिनार में सीतारमण ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने विकास परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने में बहुपक्षीय विकास बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश का विकल्प नहीं, बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के तौर पर काम करना चाहिए। भारत सरकार ने इसी सोच के तहत बुनियादी ढांचे और निवेश को



केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गर्वनरों की बैठक को संबोधित किया।

बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (बीजीएफ), हाइब्रिड एयुइटी मॉडल, क्रेडिट बढ़ाने वाले उपाय, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ परियोजनाओं में तालमेल और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद की है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई लांशत प्रावधान किए गए हैं। इनमें नए डेडिक्टेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए राष्ट्रीय जलमार्ग

और तटीय मार्गों प्रोत्साहन योजना प्रमुख हैं। इन पहलों का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स और परिवहन ढांचे को मजबूत करने के साथ निजी निवेश के नए अवसर तैयार करना है। सीतारमण ने भारत के बुनियादी ढांचे में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने लगातार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से अवसंरचना इकोसिस्टम को मजबूत किया है। पिछले एक दशक में राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स प्रणालियों, डिजिटल अवसंरचना और ऊर्जा नेटवर्क में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि विकासात्मक वित्त का भविष्य साझेदारी में निहित है। बहुपक्षीय संस्थाओं, राष्ट्रीय

सरकारों और निजी क्षेत्र की अपनी-अपनी विशिष्ट क्षमताएं हैं। इनके बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से बड़े पैमाने पर निजी पूंजी जुटाकर विकास परियोजनाओं को गति दी जा सकती है।इससे पहले आर्थिक कार्य विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने स्वागत भाषण में कहा कि विकासात्मक वित्त के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने के साथ-साथ मजबूती और दीर्घकालिक स्थिरता भी जरूरी है। सेमिनार में बहुपक्षीय संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, निजी कंपनियों, थिंक टैंक और अकादमिक जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बाद में निजी पूंजी जुटाने और विकास वित्त से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत पैनल चर्चा भी हुई।

ओपन जेल के कैदी की गोली मारकर हत्या

जयपुर। करणी विहार थाना क्षेत्र के धावास स्थित जानकी विहार इलाके में बुधवार को बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने ओपन जेल के कैदी मोहन कुमावत (40) की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने मोहन पर तीन राउंड फायर किए और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल और आसपास के रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। सामने से मौका मिलते ही उन्होंने मोहन को निशाना बनाकर फायरिंग की। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर करणी विहार के साथ भोंकरोटा और चित्रकूट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य

- बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने तीन राउंड फायर किए
- जेल लौटते समय धावास के जानकी विहार में वारदात

जुटाए और शव को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जांच में सामने आया कि मोहन कुमावत 2018 में मोती डूंगरी इलाके में महेंद्र गुर्जर की हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका था और उसे सजा हुई थी। वर्तमान में वह सांगानेर स्थित ओपन जेल में बंद था। बुधवार को वह जेल लौट रहा था। इसी दौरान धावास के जानकी विहार इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने उसका पीछा कर उसे निशाना बनाया।



जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को मिल रहे वित्तीय सहयोग के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया।

मुख्यमंत्री सीएलजी सदस्यों से आज संवाद करेंगे

जयपुर। प्रदेश में कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और पुलिस-जन सहभागिता को मजबूत करने के लिए राजस्थान पुलिस ने कम्युनिटी लायजन ग्रुप (सीएलजी) को प्रभावी बनाने की पहल शुरू की है। इसके तहत गुरुवार को जयपुर की बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्यस्तरीय ओरिएंटेशन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशभर के नव-नियुक्त सीएलजी सदस्यों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जयपुर रेंज के सभी पुलिस थानों के नव-नियुक्त सीएलजी सदस्यों को बिड़ला ऑडिटोरियम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमण व जुड़े मुकदमों की जानकारी मांगी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमणों की जानकारी पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए से 31 अगस्त तक बताने को कहा है कि यहां की जमीन से जुड़े मुकदमें किस-किस कोर्ट में किस स्तर पर चल रहे हैं। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पौन मंंदोला की जनहित याचिका सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए द्रववती नदी को दूषित बताया और साथ ही कहा की शहर में इंंदौर के मुकाबले गंदी अधिक है।

■ अदालत ने जेडीए से 31 अगस्त तक बताने को कहा है कि यहां की जमीन से जुड़े मुकदमें किस-किस कोर्ट में किस स्तर पर चल रहे हैं

कहा कि 6 माह बाद भी सरकार समय ही मांग रही है। ऐसे में सरकार को अंतिम मौका दिया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता पीएन मैंदोला ने उपस्थित होकर कहा कि नदी क्षेत्र की जमीन के कई खसरो पर अतिक्रमण हो गया है और जेडीए कईयों का नियमन भी कर रहा है। इस पर जेडीए के अधिकवक्ता ने कहा कि जेडीए की ओर से अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई लोग विभिन्न अदालतों में जाकर स्थान आदेश ले आते हैं। इस पर खंडपीठ ने जेडीए को यहां के अतिक्रमण और मुकदमों की जानकारी पेश करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार को न्यायमित्र की रिपोर्ट पर अपना रिस्पांस पेश करने के लिए समय मांगा। जिस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए

दुष्कर्म आरोपी समेत हुक्का बार संचालक गिरफ्तार

जयपुर। बजाज नगर थाना पुलिस ने अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को वारदात के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। वहीं गोपालपुरा मोड़ स्थित एक रेस्तरां में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर दबिश देकर दो संचालकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से चार हुक्के, चिलम, गठित की गई। टीम ने तकनीकी सहायता और लगातार

पाइप और विभिन्न फ्लेवर जब्त किए। डीसीपी जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई थी। एडीसीपी पास मल जैन और एसपी मालवीय नगर विनोद कुमार शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी रामधन ढोबाल के नेतृत्व में विशेष टीम

प्रयासों के बाद अंकित कुमार (26) निवासी निमभोड़ जिला कोटपूतली-बहरोड़ को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया।दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने गोपालपुरा मोड़ स्थित फिन रेस्तरां कैफे पर दबिश दी। जांच के दौरान कैफे में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित होना पाया गया। पुलिस ने मौके से चार हुक्के, चिलम, पाइप और विभिन्न फ्लेवर बरामद किए।

राज्य में “ 2 0 4 7 तक सभी के लिए बीमा ” के लिए तैयारियां शुरू

जयपुर। ‘ 2047 तक सभी के लिए बीमा ’ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य में प्रशासनिक तंत्र ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस सम्बंध में बुधवार को मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास और भारतीय बीमा बिनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) चैयरमैन श्री अजय सेठ के बीच शासन सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में वित्त (व्यय) सचिव डॉ. टीना सोनी भी उपस्थित रही।



मुख्य सचिव और आईआरडीएआई चैयरमैन के बीच रोडमैप के बारे में चर्चा हुई।

बैठक में असंगठित और वंचित वर्गों के बीच बीमा की पहुँच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज के विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों ने स्वास्थ्य दावों के त्वरित निस्तारण करने की सम्भावना पर विचार किया जिससे दावेदारों को समय पर राहत मिल सके। बैठक में लिए निर्णयों को लागू करने के लिए राज्य बीमा एवं

साधारण प्रावधानी निधि विभाग श्रीधर शर्मा की समन्वित विभागों, एजेंसियों और अन्य स्टैकहोल्डर्स की बैठक आयोजित करा। बैठक में मुख्य सचिव, अध्यक्ष , राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा परिवहन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, एसआईपीएफ निदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, अस्पताल संघों के प्रतिनिधि और प्रमुख बीमा प्रदाताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

महारानी कॉलेज में तीन दिवसीय आनंदम् कार्यशाला का आयोजन

जयपुर। महारानी कॉलेज में 10 से 12 अगस्त 2026 तक हार्टफुलनेस संगठन के सहयोग से प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के मूल्य-वर्धित पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय परिस्थितियों का आनंदम् कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में जीवन कौशल, तनाव प्रबंधन, सजगता, आत्म-जागरूकता तथा भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देना रहा। तीनों दिवस विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का संतुलित एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सामना करने के लिए व्यावहारिक तकनीकों एवं गतिविधियों से परिचित कराय गया। कार्यशाला के प्रथम दिवस में हार्टफुलनेस तकनीकों द्वारा जीवन कौशल संवर्धन विषय पर सत्र आयोजित किया गया।

बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : जोराराम कुमावत

जयपुर। पशुपालन, डेयरी गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय के चिंतन कक्ष में पशुपालन विभाग एवं डेयरी की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति के समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीन वर्षों की बजट घोषणाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की प्रगति तथा उनके समयबद्ध निष्पादन पर विस्तृत समीक्षा की गई।

■ बैठक में तीन वर्षों की बजट घोषणाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की प्रगति तथा उनके समयबद्ध निष्पादन पर विस्तृत समीक्षा की

संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया तथा निर्माणधीन परियोजनाओं, नवीन पशु चिकित्सालयों, पशु चिकित्सा उपकेंद्रों, मोबाइल वेटनरी यूनिट, पशुधन विकास, पशु बीमा, कृत्रिम गर्भाधान, पशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक सुविधाएं एवं गुणवत्तापूर्ण पशुपालन अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, उनका शीघ्र समाधान कर कार्यों में अपेक्षित गति लाई जाए। उन्होंने सभी स्तर के चिकित्सा

संस्थाओं के पट्टे जल्द से जल्द हासिल करने पर बल देते हुए कहा कि हर संस्थान के पास अपना भवन होना चाहिए जिससे पशुओं को बेहतर चिकित्सा मिल सके। कुमावत ने भेड़ ऊन विभाग की जमीन को भी पशुपालन विभाग के अंतर्गत शामिल करने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मंत्री कुमावत ने डेयरी की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन उत्पादों की मांग अधिक है उनका गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ाया जाए। उन्होंने बस्सी में स्थित सेक्स सर्टिड सीमन उत्पादन इकाई की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणाएं केवल घोषणा मात्र नहीं हैं इससे प्रदेश के किसानों और पशुपालकों का सशक्तीकरण होता है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए इन घोषणाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

नवाचारों के साथ विद्यार्थियों के कौशल विकास को मिले प्राथमिकता : एसीएस

शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्यों, नवाचारों एवं कार्ययोजना पर मंथन



अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बुधवार को जयपुर में भावी कार्ययोजना को लेकर चर्चा की।

में 400 विद्यालयों को मांडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नवाचारों को बढ़ावा देते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा सेतु कार्यक्रम की जानकारी देते हुए इसके माध्यम से

विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं विद्यालयी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। एसीएस ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएं। उन्होंने विद्यालयों में संचालित

■ एआई, डिजिटल तकनीक से स्मार्ट शिक्षा और मॉडल स्कूलों से सशक्त होगी राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था

बेहतर सुविधाओं एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाते हुए मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने तथा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। पौरामल फाउंडेशन के संस्थापक अजय पौरामल ने संस्था द्वारा राजस्थान में किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया तथा चर्चा एवं सुझावों के अनुरूप सहयोग को और बढ़ाने का आश्वासन दिया। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने समग्र शिक्षा के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं, जेंडर, हाईजीन, आधारभूत संरचना, राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समयबद्ध तैयारी, योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ उनके समग्र विकास, कौशल एवं रोजगार क्षमता पर समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया।

लोकतंत्र सेनानियों ने कठिन परिस्थितियों में लोकतंत्र की रक्षा की- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में उनके योगदान को संरक्षित करने की घोषणा की

जयपुर, 12 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपातकाल के समय लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष लोकतंत्र रक्षा की ऐतिहासिक गाथा है। उनका त्याग और समर्पण युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनेक पीढ़ियों के बलिदान के बाद देश को आजादी मिली। वहीं, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों ने राष्ट्रहित के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना कर लोकतंत्र की रक्षा की। इसलिए राष्ट्रवाद की विचारधारा उनकी तपस्या और संघर्ष से विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है।

उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि उसे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था सहज रूप से मिली है, उसके पीछे लोकतंत्र सेनानियों का त्याग छिपा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोकतंत्र सेनानी को अपने जीवन के अनुभवों को लिखित रूप में दर्ज



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया।

करना चाहिए। राज्य सरकार भी इनके योगदान को संरक्षित करेगी।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि “लोकतंत्र सेनानी समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए राष्ट्र हित जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सभी वर्गों से निरंतर संवाद करें।”

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानी समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए राष्ट्रहित जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सभी वर्गों से निरंतर संवाद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की पीढ़ी ने आपातकाल को देखा और सहा, इसलिए वे समाज एवं राष्ट्र को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। उनके अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए।

रूस ने पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर पड़े कथित प्रभाव से जुड़ा है। यह मामला यूक्रेन के डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ापोरिज्जिया क्षेत्रों में अपनी संपत्तियों और कारोबारी गतिविधियों को लेकर ओशादबैंक के दावे से जुड़ा है। बैंक का कहना है कि 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद, रूस की सैन्य कार्रवाई के कारण उसे ये संपत्तियां और कारोबारी गतिविधियां गंवानी पड़ीं। इस मध्यस्थता न्यायाधिकरण में तीन सदस्य होंगे। कोस्टा रिका की मध्यस्थ और पूर्व व्यापार मंत्री इयाला जिमेनेज को रूस और ओशादबैंक ने संयुक्त रूप से चुना है और वे न्यायाधिकरण की अध्यक्ष होंगी। यूनानी मध्यस्थ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) के प्रोफेसर स्टावरोस ब्रेकोलाकिस को ओशादबैंक ने तीसरे सदस्य के रूप में चुना है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को रूस ने अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है।



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

सरकार ने एफसीआर बिल पारित कराने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगरानी को विधेयक का प्रमुख आधार बताया है।

लगातार विपक्षी विरोध, विधेयक को पूरी तरह वापस लेने की मांग तथा सिविल सोसायटी और चर्च संगठनों की आपत्तियों के बीच केन्द्र ने जेपीसी का रास्ता चुना। इन समूहों को आशंका है कि संपत्तियों को जब्त करने जैसी व्यवस्था के तहत, पहले से किए गए निवेश भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सुनवाई या न्यायिक निर्णय का प्रावधान नहीं है।

12 अगस्त, 2026 को केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को जेपीसी को सौंपने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे हंगामे के बीच लोकसभा ने ध्वनिमत से मंजूर कर लिया। 31 सदस्यीय समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। समिति को

‘घर-घर जाके कूड़ा उठाने की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसलिए किए गए, ताकि याचिकाकर्ता को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सके। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि जून 2026 में जारी किए गए टेंडर में शर्तों में फेर बदल इसलिए किया गया, ताकि याचिकाकर्ता निविदा में भाग न ले सके।

दूसरी ओर नगर निगम की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता का मामला अपरिक्व है, क्योंकि तीसरी निविदा के संदर्भ में नगर निगम ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। उल्लेखनीय है कि तीसरी निविदा में जिस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है, उसे भी टेंडर देने में नगर निगम को तीन वर्ष में 54.5 करोड़ की लागत उठानी पड़ेगी। जबकि याचिकाकर्ता को 2024 में एक वर्ष के लिए जो अनुबंध

किया गया था उसके अनुसार नगर निगम को 12.8 करोड़ की लागत आई थी। और इन आंकड़ों के अनुसार, नगर निगम को 39 करोड़ की लागत उठानी पड़ती, अगर उक्त टेंडर याचिकाकर्ता को तीन साल के लिए दिया जाता तो। सभी तथ्यों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि नगर निगम द्वारा दो बार बिना वजह टेंडर रद्द किये जाने से याचिकाकर्ता आहत हुआ है, क्योंकि निविदाओं में पब्लिक फंड का उपयोग होता है, इसलिए अधिकारी मनमाने तरीके से रद्द नहीं कर सकते। उन्हें टेंडर रद्द करने का स्पष्ट कारण देना आवश्यक होता है। अदालत ने कहा कि जिस तरह से निविदा की शर्तों में फेर बदल किया गया है उससे जाहिर है कि याचिकाकर्ता को निविदा में भाग लेने से वंचित रखना और किसी और को अवांछित लाभ पहुंचाना ही इसका उद्देश्य

था। अदालत ने कहा कि नगर निगम द्वारा मार्च 2026 में जारी दूसरी निविदा को ही पूर्ण किया जाए और जून में आमंत्रित तीसरी निविदा के नोटिस को रद्द किया है।

टाटा संस के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा, “मैंने बोर्ड से जल्द उत्तराधिकारी तय करने को कहा है, ताकि नेतृत्व का उचित और सुचारु हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके।” टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच बोर्ड में प्रतिनिधित्व, समूह की रणनीति और माइनॉरिटी शेयर होल्डर शापूजी पालोनजी के प्रस्तावित एग्जिट को लेकर मतभेद चल रहे हैं। टाटा संस टाटा समूह की मुख्य निवेश होल्डिंग कंपनी है, जबकि टाटा ट्रस्ट्स के पास कंपनी की करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह मामला कुछ हद तक घुमावदार तर्क पर आधारित था। अमेरिकी शिकायत में कहा गया था कि अडानी ने अपने शेयरधारकों और निवेशकों को रिश्वत के भुगतान की जानकारी नहीं देकर उन्हें गुमराह किया। इस तरह यह सिक्यूरिटीज फ्रॉड और निवेशकों को धोखा देने की मंशा का मामला बनता था। दूसरी ओर, उन्होंने यह भी माना कि कंपनी ने यह आश्वासन दिया था कि वह रिश्वतखोरी में शामिल नहीं है।

तथापि, कुछ अधिकारियों का तर्क था कि रिश्वत के भुगतान का मुख्य मुद्दा, भले ही वह सच हो, अमेरिकी कानूनों के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और पूरी तरह भारतीय कानून के अधिकार क्षेत्र में आता था। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा था कि यह एक विदेशी मामला था

और जांच में पता चला कि ऐसी कोई रकम हस्तांतरित नहीं की गई थी, जिस पर अमेरिका में कानूनी कार्रवाई की जा सके। न ही प्रतिभूतियों में कोई नुकसान हुआ था। न्याय विभाग का कहना था कि यह मामला असल में “नाम खराब करने और शर्मिंदा करने” की कोशिश थी, और इसका मकसद कभी भी गंभीरता से मुकदमा चलाना नहीं था। यह भारतीय कॉरपोरेट जगत की कुछ बड़ी कंपनियों को बदनाम करने की किसी बड़ी चाल का हिस्सा भी हो सकता है।

अडानी ग्रुप देश के सबसे कामयाब कॉरपोरेट घरानों में से एक है और कई देशों में उसका कारोबार फैला हुआ है। अडानी समूह के पास ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी कोयला खदान है, वह कई देशों में बंदरगाहों का संचालन करता है और अमेरिकी बाजार में भी बड़े

निवेश की योजना बना रहा है। गौतम अडानी को व्यक्तिगत रूप से एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है और उनकी संपत्ति का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका में मुकदमा चलने के बावजूद, हाल के दिनों में अडानी समूह का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है। फ़ैडरल कोर्ट का फैसला आने के बाद गौतम अडानी ने अमेरिकी न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया।

टेक इट और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमित शाह का कहना है कि “टेक इट और लीव इट।”

राहुल का जवाब है कि “वी हैव लैफ्ट इट।” गतिरोध जारी है।

हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और समाजवादी पार्टी सहित, अन्य विपक्षी दल अब भी विधेयक को पूरी तरह समाप्त किए जाने की मांग पर कायम है। के.सी. वेणुगोपाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का आरोप है कि यह विधेयक गैर-सरकारी संगठनों

(एनजीओ) और अल्पसंख्यक संस्थानों, विशेष रूप से ईसाई संगठनों, को असमान रूप से निशाना बनाता है और वास्तविक नियामक जरूरतों के बजाय, व्यापक राजनीतिक हितों की पूर्ति करता है।

कुछ विपक्षी नेताओं ने यह कहते हुए जेपीसी को भी खारिज किया है कि ऐसी समितियों में सतारूढ़ दल का वर्चस्व होने के कारण विपक्ष का प्रभाव सीमित रह सकता है।

इससे पहले, चर्च के प्रतिनिधि मंडलों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर विधेयक को वापस लेने या इसकी विस्तृत जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने धर्मार्थ, शैक्षणिक, चिकित्सा और धार्मिक संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर अपनी चिंताओं को सामने रखा था।

जेपीसी का रास्ता अपनाकर सरकार को अब विचार-विमर्श, हितधारकों की सुनवाई और विधेयक में संभावित संशोधनों के लिए समय मिल गया है। साथ ही, इससे मानसून सत्र के अंत में सदन के पटल पर तत्काल टकराव की स्थिति से भी बचा जा सका है।

ऑटो -टैक्सी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मराठी भाषा की जानकारी नहीं होने पर डाइविंग अनुमति को तीन महीने तक निलंबित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, बार-बार नियम तोड़ने पर अनुमति या लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किया गया है।

TRUE VALUE

इस स्वतंत्रता दिवस कार लेना हुआ आसान। सिर्फ ₹59 प्रतिदिन* की आसान किश्तों में।

CELEBRATING 60Lakh+ STORIES OF TRUST

Download on the App Store

GET IT ON Google play

True Value ऐप यहाँ डाउनलोड करें।

ट्रस्ट

☒ वेरिफाइड कार हिस्ट्री**

☒ 3 फ्री सर्विसेज** 5000++ से अधिक मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशनों पर उपलब्ध

क्वालिटी

☒ 376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

☒ 1 साल तक की वारंटी**

आसान फाइनेंस विकल्प* उपलब्ध हैं।

TRUE VALUE CERTIFIED

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

ALWAR: NEAR ALWAR PUBLIC SCHOOL, JAIPUR ROAD, ALWAR, MG MOTORS: 7240012934, 7728892248, 7073130666 | OPPOSITE MATILA POLICE STATION ALWAR BYPASS ROAD BHIWADI, FORTUNE CARS: 8875001550, 9214094335 | MANHAR VILLA, NEAR JAIL CIRCLE, VIJAY NAGAR ROAD, ALWAR, FORTUNE CARS: 7230029310, 7230029304 | BHARATPUR: AFTER BARSO, BEFORE SHAHEED PETROL PUMP, AGRA ROAD, BHARATPUR, T.M. MOTORS: 9772965965, 9772772999.

*नियम एवं शर्तें लागू। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया निकटतम डीलरशिप पर संपर्क करें। **वेरिफाइड कार हिस्ट्री और वारंटी केवल ट्रू वैल्यू प्रमाणित कारों पर लागू हैं। निशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। दर्शाई गई छवियाँ केवल प्रतिनिधिक उद्देश्य के लिए हैं। *अचर राशि ₹1 00 000 मानी गई है। *अचर की अवधि 84 महीने @ROI 11% वार्षिक व्याज दर पर ली गई है। *खान पमेंट कार के मूल्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। *वाहन पर काला सीसा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है। *फाइनेंस पूरी तरह बैंक या वित्तीय संस्था की मंजूरी पर निर्भर है और ग्राहक प्रोफाइल के अनुसार बदल सकता है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. **RAJHIN/2008/27147** जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्यद मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्स्टीटयल परिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908